वर्ष-10//अंक-21// जून//2023

ISSN 2454–5805

₹20/-

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

छत्तीसगढ़ में सबका बढ़ता मान

छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को मिला राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड

बाल अधिकारों की रक्षा में युवाओं की सक्रिय भूमिकाः श्रीमती तेजकुंवर नेताम

→05

बेरोजगारी से मुक्ति की ओर बढ़ा छत्तीसगढ

→08

'कका' के राज में 'नोट बैंक' बने गौठान...

→25

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के नये आयाम

Chai Signal

Taste Our Delicious Food at your Doorstep!

Order on SWIGGY zomato

www.chaisignal.com

Shop No.24, Katora Talab Garden, Raipur (C.G.)

Follow Us:

आम आदमी पत्रिका

वर्ष-10//अंक-21// जून 2023

प्रबंध संपादक	:	उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज	:	प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	:	नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर	:	प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर	:	देवेन्द्र देवांगन
मैग्ज़ीन डिज़ाइनर	:	आइज इवेंट्स
मार्केटिंग मैनेजर	:	किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन	:	काजल सिंह
अकाउंट असिस्टेंट	:	प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर	:	योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छतीसगढ़

फोन : 0771-4044047

ईल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

जून 2023

इस अंक में

रायपुर. छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार गौठानों से आमदनी, सेवा-सत्कार और खुशियां बांट रही है. शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना पशुपालकों की तकदीर लिख रही है. गौठानों से लोगों को वित्तीय मदद के साथ-साथ रोजगार भी मिल रहा है. गोठानों से ग्राम स्वावलंबन का सपना साकार हो रहा है. गौठानों ने गौवंश और गौ पालकों की तकदीर बदलकर रख दी है. गायों को गर्मी से बचाने शेड और फॉगर की सुविधाएं की गई हैं. 06

जल से 'जीवन' बांट रही सरकार 27 जिलों में जल जीवन मिशन बना वरदान 10

रायपुर. एक भजन है, जिसमें कवि कहता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा.

राजीव युवा मितान क्लबों को मिलेगी 7-71 करोड़ रूपए की राशि 12

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नें राज्य के 13 जिलों के 3085 राजीव युवा मितान क्लबों को 7 करोड़ 71 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे.

युवाओं को मिला बड़ा संबल: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरूआत की 14

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो गई है.

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के 5 कारण, कैसे फेल हुई BJP की रणनीति? 16

कर्नाटक में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की.

झुग्गी बस्ती से निकलकर श्रमिकों के बच्चों ने बनायी अंतर्राष्ट्रीय पहचान 28

रायपुर के रहने वाले निखिल नायक, बीरू बाग और किशन महानंद रायपुर की झुग्गियों से निकलकर कनाडा और हांगकांग में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.

बृजमोहन ने राजधानी में ही खोली सरकार के गोधन न्याय योजना की पोल 18

रायपुर. वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की राजधानी रायपुर में ही पोल खोलकर रख दी है।

ये रेल हादसा है रेलवे के लिए सबक

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बेहद दुखद और शर्मनाक हादसा दर्ज हो गया. ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित बहानागा बाजार स्टेशन एक बहुत अविश्वसनीय हादसे का गवाह बन गया. इस हादसे को समझने में ही लगभग एक दिन का समय लग गया और जो गलती हुई है, उसका आकार-प्रकार तय करने में पता नहीं कितना समय लगेगा? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया कि दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हुई है. हादसे की अगली सुबह तक 290 लोगों की मौत हुई है और करीब 1,000 लोग घायल हैं. रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है और घटना की वजहों के साथ-साथ इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है. आमतौर पर रेलवे सामूहिक जिम्मेदारी के तहत दोषी या जिम्मेदार व्यक्ति के नाम उजागर करने से बचता है, पर अब यह परिपाटी बदलनी चाहिए. रेलवे ही नहीं, हर विभाग में जो गैर-जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें चिह्नित करना चाहिए. बदलते दौर में सरकारों की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की सेवा में नाकारा लोगों को बर्दाश्त न किया जाए.

साल 1995 के बाद यह सबसे घातक रेल दुर्घटना है और इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. पहले भी सुधार के अवसरों को हमने गंवाया है, पर अब सुधार से मुंह चुराने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है. दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला भारत और उसका जरूरत से ज्यादा दबाव झेलता रेल ढांचा छटांक भर लापरवाही भी नहीं बर्दाश्त कर सकता. प्रधानमंत्री का दुर्घटनास्थल पर जाना और वहां रेल मंत्री का लगातार बचाव कार्य में जुटे रहना बेहतर संकेत है. सेवा के मामले में दिखावे का दौर अब पीछे छूट जाना चाहिए और हर सेवा को चाक-चौबंद करना प्राथमिकता होनी चाहिए. भारत अगर सुविधा व सेवा को सुरक्षित बनाने पर पूरा ध्यान लगाए, तो ऐसे हादसों से हम बच सकते हैं, लेकिन आम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपनी सुरक्षा, सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ही वोट देते हैं? समय बदल रहा है, जनता की सुरक्षा के प्रति हर नेता को सजग होना चाहिए. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गईं. वह कोशिश में लग गईं कि जान गंवाने वालों की संख्या को बढ़ाकर बताएं, ताकि राजनीति चमकाने में सुविधा हो. वैसे, वह रेल मंत्री रह चुकी हैं, तो आज जो रेल दुर्घटना हुई है, उसमें उनका भी कुछ तो योगदान बनता होगा? वस्तुत यह रेल हादसा राजनीति नहीं, बल्कि नीति और नीयत का विषय है.

> मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब बेरोजगारी मुक्त राज्य की ओर बढ़ रहा है. देश में सबसे कम बेरोजगार वाले राज्यों की सूची में अब छत्तीसगढ़ का नाम भी आने लगा है. सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी) आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 की बात करें तो राज्य में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 22.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था. ठीक चुनाव से पहले सितंबर 2018 में यह आंकड़ा 22.2 प्रतिशत था. लेकिन जब दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जिम्मेदारी संभाली तो इन आंकड़ों में धीरे-धीरे कमी आती गई.

भूपेश सरकार की नीतियों ने बेरोजगार युवाओं के लिए खोले रोजगार के रास्ते

☞ बेरोजगारी से मुक्ति की ओर बढ़ा छत्तीसगढ

वर्ष 2023 की बात करें तो जनवरी में यह आंकड़ा 05, फरवरी और मार्च माह में यह आंकड़ा 0.8 पर बना हुआ है. तब और अब में अंतर साफ है. कोरोना काल के दौरान भी जब देशभर में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, तो यहां सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए इस पर नियंत्रण बनाए रखा था. आज स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देशभर में अर्थशास्त्रियों के लिए अध्ययन का विषय बनी हुई है.रोजगारी दर पर अंकुश को लेकर जब छत्तीसगढ़ की बात होती तो सीएम भूपेश की उन तमाम योजनाओं और फैसलों का जिक्र होता है जो सीधे लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने से जुड़ी है. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मिलेट्स की समर्थन मूल्य में खरीदी, लघु वनोपज समर्थन मूल्य में खरीदी, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में बढ़ोतरी से लेकर डीएमएफ फंड को बुनियादी जरूरतें और आजीविका आधारित अधोसंरचनाओं में खर्च वाले फैसलों का होता है. इन योजनाओं के जरिए राज्य में हर वर्ग को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया. इनके जरिए ग्रामीण कारोबार और स्वरोजगार के अवसर पाए गए. जिससे बेरोजगारी दर कम करने में काफी मदद मिली.

रोजगार नीति से पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव

सुराजी ग्राम योजना के नरवा-घुरुवा-बारी कार्यक्रम के तहत गौठान बनाए गए, जिन्हें बाद में ग्रामीण औद्योगिक पार्क में बदला गया. परंपरागत कारोबार की अब सुविधाएं बढ़ गई. ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थ की सबसे बड़ी नींव कहलाई, जिनके जरिए सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर दिए गए. इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार के 100 दिवस की व्यवस्था को निश्चित किया गया और ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड बनाए गए.

घटते क्रम में बेरोजगारी दर

इनसे गांवों में निश्चित रोजगार मिलने लगा. वनाधिकार पत्र के जरिए अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनवासियों को संसाधन उपलब्ध करवाए गए. औद्योगिक नीतियों में बदलाव किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित किए जा सकें. शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल-कॉलेजों की शुरुआत से बड़े पैमाने पर रोजगार मिला. विभागों, निगम-मंडलों, आयोगों, समितियों आदि में निर्धारित व्यवस्था और व्यापम और लोक सेवा आयोग के जरिए मिलने वाली नौकरी के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनकर समय पर परीक्षाएं करवाई गई. ताकि नौकरियां निरंतर मिलती रहे. इन तमाम प्रयासों का असर ही बेरोजगारी के आंकड़ों को धीरे-धीरे कम करता गया.

गौठानों ने बदली गौवंश और गौ पालकों की तकदीर, गायों को गर्मी से बचाने शेड और फॉगर की सुविधा

☞ महिला समूह भी हो रहे खुशहाल, जानिए बघेल सरकार ने कैसे बदली सूरत

रायपुर. छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार गौठानों से आमदनी, सेवा-सत्कार और खुशियां बांट रही है. शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना पशुपालकों की तकदीर लिख रही है. गौठानों से लोगों को वित्तीय मदद के साथ-साथ रोजगार भी मिल रहा है. गोठानों से ग्राम स्वावलंबन का सपना साकार हो रहा है. गौठानों ने गौवंश और गौ पालकों की तकदीर बदलकर रख दी है. गायों को गर्मी से बचाने शेड और फॉगर की सुविधाएं की गई हैं. इसके साथ ही महिला समूह भी खुशहाल हो रहे हैं. आइये जानते हैं बघेल सरकार ने कैसे बदली सीरत और सूरत ?

गौकाष्ठ और गोबर से 32 तरह के उत्पाद तैयार

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान योजना का क्रियान्वयन करते हुए रायपुर नगर निगम द्वारा फुंडहर, गोकुल नगर, जरवाय के गौठानों में गौवंशीय पशुओं के बेहतर रख-रखाव के साथ ही आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अभिनव पहल की जा रही हैं. गोकुल नगर गौठान में महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं गौमूत्र का अर्क तैयार करने के साथ ही साथ ब्रम्हास्त्र जैविक कीटनाशक, पौधों के पोषण में उपयोगी जीवा अमृत, गौकाष्ठ और गोबर से 32 तरह के उत्पाद तैयार कर अपने आर्थिक स्तर में बड़ा बदलाव ला रही है.

लावारिस गायों को रखने की सभी व्यवस्थाएं

जरवाय गौठान में दीवारों की पुताई के लिए पेंट तैयार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अब नगर निगम सहित शासकीय भवनों को इस पेंट से ही पुताई की जा रही है.

फुन्डहर गौठान, जहां परित्यक्त, घायल ,बीमार व सड़कों पर विचरण करते लावारिस गौ वंशियों को रखने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं. इस गौठान में 281 गायें हैं.

गर्मी के मौसम में ठंडक देने फॉगर की व्यवस्था

गर्मी के मौसम में इन्हें ठंडक देने फॉगर की व्यवस्था के साथ ही सब्जी बाजार से चारे, तरकारी आदि भी नगर निगम द्वारा खरीदकर दिए जा रहे हैं. इस गौठान में 24 घंटे पशु चिकित्सक की सेवा उपलब्ध है. 10 कर्मचारी गौठान में नियमित साफ-सफाई, चारे, पानी हेतु शिफ्ट में काम करते हैं. गायों की संख्या बढ़ने पर इन पशुओं को ग्रामीण गौठानों में स्थानांतरित किया जाता है. सड़कों पर लावारिस हालत में यहां लाए गए पशु की पहचान कर पशु मालिक नियत जुर्माना अदा कर वापस भी ले जाते हैं.

स्व-सहायता समूहों का जीवन स्तर भी बदला

रायपुर नगर निगम द्वारा इस समय शहर में तीन गौठानों का संचालन किया जा रहा है. इन गौठानों में परित्यक्त व दुर्घटना में घायल गौधन के देखभाल की व्यवस्था की जाती है. इन गौठानों के बेहतर प्रबंधन से न केवल गौवंशीय पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि गौ सेवा में जुटे स्व-सहायता समूहों का जीवन स्तर भी बदला है. गोकुल नगर में "एक पहल महिला स्व-सहायता समूह" की महिलाएं अर्क निकालने 4 रूपये लीटर पर गौमूत्र क्रय कर रही हैं.

जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र की अत्यधिक मांग

समूह द्वारा उत्पादित जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र की भी अत्यधिक मांग है और 50 रूपये लीटर में इस कीटनाशक की बिक्री इस गौठान से की जा रही है. पौधों के लिए उपयोगी जीवा अमृत नामक पोषक भी इस गौठान में उत्पादित हो रहा है. महिलाएं बताती है कि 50 रूपये लीटर बिकने वाले इस जीवा अमृत में पौधों को जीवन प्रदान करने की अद्भुत शक्ति है.

बिलौना घी, पनीर, दूध, दही से गौठान की अपनी अलग पहचान

इन महिलाओं ने बरसों पुराने मोटे ठूंठ को इसी गौठान में ही वृक्ष के रूप में पुनर्जीवित करने का कार्य भी किया है. महिला समूह द्वारा निर्मित गोबर से बने सूटकेश, दीये, मूर्तियां, पूजन सामग्री, सजावटी सामान की मांग भी बहुतायत है. इसके अलावा वैदिक पद्धति से तैयार बिलौना घी, पनीर, दूध, दही से गौठान की अपनी अलग पहचान बनी है.

वंश वृद्धि के लिए गौठान में कृत्रिम गर्भाधान पद्धति

महिला समूह की सचिव श्रीमती नोमिल पाल बताती है कि कई घायल गौवंशीय के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार के बाद अब इन पशुओं के लिए गौठान अब स्थायी बसेरा है. घायल अवस्था में दो साल पहले गौठान पहुंचे मुर्रा नस्ल की भैंस अब बच्चे को जन्म देने वाली है. गौवंशीय के वंश वृद्धि के लिए गौठान में कृत्रिम गर्भाधान पद्धति अपनायी जाती थी, किन्तु अब इनके जोड़े भी गौठान में तैयार हो चुके हैं.

छत्तीसगढ़ की कोसली नस्ल के गाय

इस गौठान में छत्तीसगढ़ की कोसली नस्ल के गाय, बछड़ों के अलावा, साहीवाल, थारपार, गिर नस्ल के गौधन भी हैं, जो घायल अवस्था में पशु पालकों द्वारा सड़कों पर छोड़ दिए गए थे, यही गौधन अब स्वस्थ्य होकर दुग्ध व अन्य उत्पादों से महिला समूहों के लिए नये आर्थिक स्त्रोत सृजित करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

दीवारों को रंगने के लिए गोबर से पेंट का उत्पादन

जरवाय के गौठान में दीवारों को रंगने के लिए गोबर से पेंट का उत्पादन किया जा रहा है. इस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्वयं पहल की है. उनके निर्देश पर रायपुर नगर निगम मुख्यालय सहित अन्य भवनों की दीवारों को गोबर से बने पेंट से ही रंगने की शुरूआत की जा चुकी है.

स्व-सहायता समूह के जीवन में भी बड़े बदलाव की आहट

समूह की महिलाएं बताती है कि यह पेंट किसी भी रसायनिक पेंट से ज्यादा उपयोगी है. गोबर पेंट किफायती होने के साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली पेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि कैमिकल पेंट की तुलना में अधिक आकर्षक और प्रभावशाली है. समूह की महिलाएं इसे गौठान योजना का बेहतर उत्पाद मानते हुए इसे कृषि आधारित उद्योगों में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखती है. इन सब प्रयासों से गौठानों की आत्म निर्भरता बढ़ रही है और इससे जुड़े स्व-सहायता समूह के जीवन में भी बड़े बदलाव की आहट है.

CG में हो रही धन की वर्षा ! मेहनतकशों के खाते में 445 करोड़ 14 लाख का भुगतान

'कका' के राज में 'नोट बैंक' बने गौठान...

रायपुर. गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा छत्तीसगढ़ के युवा, बुजुर्ग, किसान और महिलाओं के लिए सौगात बन कर आई है. प्रदेश के मुखिया की दूरंदेशी का असर प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है. किसानों के खाते में पैसे बरस रहे हैं. महिलाओं को रोजगार मिल रहा है. गौठान खुशहाल हो रहे हैं. चारों तरफ से छत्तीसगढ़ को गढ़ने का काम किया जा रहा है. गौठान आजीविका सृजन और जीवनयापन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी योजना, जिसके अंतर्गत नरवा-गरवा, घुरवा-बारी संचालित है. योजना ने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी ही बदल दी है. आज इस योजना से गांव-गांव में महिलाओं के पास रोजगार है, आर्थिक उन्नति है, मान-सम्मान है.

सुराजी गांव योजना वरदान बनकर उभरी

नरवा, गरवा, घुरुवा, बाड़ी के संरक्षण और संवर्धन के किए सुराजी गांव योजना वरदान बनकर उभर रही है. भूपेश बघेल 21 मई को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को फिर 13.57 करोड़ रूपये जारी करेंगे. गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अब तक 445 करोड़ 14 लाख रूपए का भुगतान हो चुका है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली गति

राज्य सरकार गौठान के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस तरह से गति दी है, इसका सीधा फायदा आज ग्रामीणों को विशेषकर महिलाओं को हो रहा है. गौठान में काम एक तरह से महिलाओं के नाम है. स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए गौठान में ढेरों गतिविधियां संचालित हैं. जहां से महिलाएं को रोजगार भी और स्व-रोजगार भी है. मतबल वह महीने के मासिक वेतन पर भी काम कर रही हैं, वहीं खुद का व्यवसाय कर उद्यमी भी बन रही हैं.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो रही मजबूत

किसान परिवार से जुड़े छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'सुराजी गांव योजना' की परिकल्पना की है. उनके कुशल मार्गदर्शन में यह योजना तेजी से क्रियान्वित की जा रही है. मुख्यमंत्री के निर्देशन में किसानों से धान खरीदी, उनकी कर्ज माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी नवीन योजनाओं से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है.

गौठान जीविकोपार्जन और जीविका का सशक्त माध्यम

जल संरक्षण, पशुपालन, मृदा स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन की गतिविधियों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ा गया है. आमजन के सहयोग से योजना को सफल बनाने के लिए सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी के संरक्षण व संवर्धन का अभियान शुरू किया गया है. साकृतिक परंपरा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसे एक अभियान के रूप में लिया है.

हरेली के दिन गोधन न्याय योजना का शुभारंभ

राज्य सरकार द्वारा 20 जुलाई 2020 को हरेली के दिन गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया. इसके तहत गौठान समितियों की खरीदी एक रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है. ग्राम सुराजी में स्थापित गौठानों के माध्यम से 2 प्रति किग्रा. गौठानों में इसी गोबर से स्वयं सहायता समूहों द्वारा वर्मीकम्पोस्ट, सुपरकम्पोस्ट एवं सुपरकम्पोस्ट प्लस का उत्पादन किया जाता है. वर्मी कम्पोस्ट 10 रुपये प्रति किलो, सुपर कम्पोस्ट 6 रुपये प्रति किलो और सुपर कम्पोस्ट प्लस 6.50 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों को बेचा जा रहा है.

किसानों के खेतों में जैविक खेती

इस योजना के तहत गोबर से बनी वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट जैसे जैविक खादों के प्रयोग से किसानों के खेतों में जैविक खेती की दिशा में उत्कृष्ट पहल की जा रही है. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके, भूमि, जल, वायु, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करके, खाद्य श्रृंखला में रसायनों के अवशेषों को कम किया जा रहा है, जिससे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार की पूरी संभावना है. खरीफ वर्ष 2023 के लिए रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर किसानों को गुणवत्तापूर्ण वर्मीकम्पोस्ट उपलब्ध कराने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं.

सुराजी ग्राम योजना, नरवा, गरुवा, घुरूवा, बाड़ी के संरक्षण और संवर्धन का अभियान

गोधन न्याय योजना के तहत बने गौठानों में न केवल गोबर की खरीद, खाद बनाकर बेचा जा रहा है,

बल्कि इससे इतर आजीविका सृजन के नए मानक अपनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर, मजबूत और मजबूत हो रही है. गौठान अब केवल गोबर क्रय-विक्रय केंद्र ही नहीं रह गए हैं, बल्कि जीविका का सशक्त साधन भी बन गए हैं.

अरहर और फूलों की खेती

वर्मी कम्पोस्टिंग एवं बिक्री के अतिरिक्त सब्जी उत्पादन, मशरूम स्पॉन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, अंडा उत्पादन, केंचुआ उत्पादन, मसाला निर्माण, कैरीबैग एवं दोना-पत्ती निर्माण, बेकरी निर्माण, अरहर एवं फूलों की खेती सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इन गौठानों में किया गया. समूह के सदस्य अच्छा काम कर रहे हैं. जिले के कुरुद विकासखण्ड के गौठानों में आजीविका गतिविधियों की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्पादन कार्य की लागत को अलग कर इन समूहों को लगभग लाखों रुपये की अतिरिक्त आय हुई है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है. .

लगातार पुरस्कार

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (ई-गवर्नेंस पर विशेष रुचि समूह) द्वारा दिया जाता है. गोधन न्याय योजना का चयन राज्य एवं परियोजना श्रेणी में किया गया है. गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना को पूर्व में "स्कॉच गोल्ड अवार्ड" और "नेशनल लेवल इनोवेशन अवार्ड" भी मिल चुका है.

स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक बढ़ी

गोधन न्याय योजना के तहत स्वावलंबी गौठान न केवल गोबर उपार्जन में सहभागी हो रहे हैं, बल्कि निरंतर प्रगति भी कर रहे हैं. विगत कई पखवाड़े से गोबर की खरीद के लिए दी जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक बढ़ने लगी है. आज की स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक गौठान स्वावलंबी हो गए हैं, जो अपने कोष से गोबर एवं गोमूत्र क्रय करने के साथ-साथ गौठानों की अन्य गतिविधियों को अपने कोष से पूर्ण कर रहे हैं.

जल से 'जीवन' बांट रही सरकार
27 जिलों में जल जीवन मिशन बना वरदान

• 22.40 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन • जानिए भूपेश सरकार ने कैसे बहाई 'अमृत' की धारा ?

रायपुर. एक भजन है, जिसमें कवि कहता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा. कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के कुछ हिस्सों में थे, जहां के लिए लोग पानी की एक-एक बूंद-बूंद के लिए तरस रहे थे. गंदे पानी पीकर गुजर-बसर कर रहे थे, लेकिन इन सबके बीच भूपेश सरकार ने बदहाल और बेबस लोगों की जिंदगी में अमृत घोल दी. गांवों में घर-घर नल जल कनेक्शन भेज खुशियों की धारा बहाई है. भूपेश सरकार जल से 'जीवन' बांट रही है. 27 जिलों में जल जीवन मिशन को वरदान साबित कर दिखाया है. 22.40 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देकर 'अमृत' धारा बहाई है.

घरेलू नल कनेक्शन देने में सबसे आगे जांजगीर-चांपा

बता दें कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है. प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक 22 लाख 40 हजार 711 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं. इसके साथ-साथ राज्य के 43 हजार 942 स्कूलों, 41 हजार 676 आंगनबाड़ी केन्द्रों और 17 हजार 289 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सबसे अधिक 1 लाख 95 हजार 387 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में सबसे आगे है.

जल जीवन मिशन योजना बनी वरदान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए सभी जिलों में कार्ययोजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं. इस मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के अतिरिक्त स्कूल, उप-स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही साथ जल जीवन मिशन के कार्यों का क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी डॉ. एस. भारतीदासन और मिशन संचालक आलोक कटियार द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है.

कोरिया जिले में नल कनेक्शन से घर-आंगन में ही मिल रहा शुद्ध पेयजल

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सोलर आधारित एवं रेट्रोफिटिंग नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीणों के जीवन में हुए बदलाव के परिणाम सामने आ रहे हैं. वनांचलों के दूरस्थ पहुंचविहिन इलाकों में भी जल जीवन मिशन के तहत टेपनल के माध्यम से ग्रामीणों को घर-घर शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है. कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन का काम प्राथमिकता से किया गया.

गर्मी के दिनों में हैंडपंप ही रहता था सहारा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम पंचायत चिरगुड़ा तथा कोचिला में सोलर आधारित योजना के तहत ग्रामवासियों का सपना साकार हुआ. अब उन्हें अपने घर-आंगन में ही शुद्ध पेय जल मिलने लगा है. केवटापारा निवासी हितग्राही चन्द्रवती विश्वकर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन लगने से पूर्व उनको पानी हैण्डपंप से लाना पड़ता था, लेकिन गर्मी के दिनों में हैंडपंप के पानी का स्तर नीचे हो जाने के कारण पानी के लिये दूर जाना होता था.

भूपेश सरकार का जताया आभार

जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन लग जाने से अब शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है. जल जीवन मिशन के उद्देश्य की सार्थकता ग्रामीण महिलाओं के चेहरों पर खुशियों के रूप में झलकने लगी है. घरेलू नल कनेक्शन से लाभान्वित हितग्राही महिला राम बाई ने बताया कि नल कनेक्शन से अब पानी की सारी समस्या खत्म हो गई है, इसके लिए मैं शासन की बहुत-बहुत आभारी हूं.

किस जिले में कितने लाख नल जल कनेक्शन ?

जल जीवन मिशन के तहत अब तक राजनांदगांव जिले में 1 लाख 59 हजार 708, रायपुर जिले में 1 लाख 30 हजार 123, रायगढ़ जिले में 1 लाख 26 हजार 153, धमतरी जिले में 1 लाख 19 हजार 022, बलौदाबाजार-भाटापारा में 1 लाख 9 हजार 568, महासमुंद जिले में 1 लाख 7 हजार 100 नल जल कनेक्शन हैं. वहीं कवर्धा 1 लाख 4 हजार 725, दुर्ग 97 हजार 237, बिलासपुर जिले में 94 हजार 880 और बेमेतरा जिले में 94 हजार 654 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

मुंगेली में 88 हजार 606 नल जल कनेक्शन

इसी तरह बालोद में 88 हजार 978, मुंगेली में 88 हजार 606, गरियाबंद 75 हजार 915, जशपुर में 65 हजार 156, सरगुजा जिले के 62 हजार 253, बलरामपुर में 62 हजार 007, कांकेर 61 हजार 030, बस्तर में 60 हजार 542, कोरबा में 59 हजार 586, सूरजपुर में 57 हजार 937 नल जल कनेक्शन की सुविधा दी गई है.

नारायणपुर में इतने हजार कनेक्शन

इसके साथ ही कोरिया में 56 हजार 383, कोण्डागांव में 55 हजार 450, बीजापुर 22 हजार 317, सुकमा में 23 हजार 376, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 22 हजार 278, दंतेवाड़ा में 20 हजार 727 और नारायणपुर जिले में 14 हजार 613 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

राजीव युवा मितान क्लबों को मिलेगी 7.71 करोड़ रूपए की राशि

'रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई को दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम सांकरा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित भरोसे का सम्मेलन में राज्य के 13 जिलों के 3085 राजीव युवा मितान क्लबों को 7 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि जारी करेंगे.'

☞ 13 जिलों को मुख्यमंत्री भूपेश करेंगे राशि का भुगतान

गौरतलब है कि युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के उद्देश्य से राजीव युवा मितान क्लबों का गठन किया गया है. वर्तमान में प्रदेश में 13 हजार 242 राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है. राजीव युवा मितान क्लब को विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए प्रत्येक तीन माह में 25 हजार रूपए के मान से सालाना एक लाख रूपए प्रत्येक क्लब को दिए जा रहे हैं. योजना प्रारंभ होने से अब तक राजीव युवा मितान क्लबों को 60 करोड़ 18 लाख रूपए की राशि उपलब्ध करायी गई है.

राजीव युवा मितान क्लब में रचनात्मक गतिविधियों के आयोजन से उत्साहित हुए युवा राजीव युवा मितान क्लब योजना के माध्यम से गांवों, कस्बों के साथ-साथ शहरों में विभिन्न सांस्कृतिक, रचनात्मक गतिविधियां तथा छत्तीसगढ़ के रीति-रिवाज को सहेजने और पारंपरिक खेलकूद के आयोजन से युवा उत्साहित है. युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग हो रहा है और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को जानने, और समझने के पर्याप्त अवसर युवाओं को मिल रहा हैं. अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहकर युवा क्षेत्र व समाज के नवनिर्माण में अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग कर प्रदेश के प्रगति में अहम् भागीदारी निभा रहे हैं.

लोगों में परस्पर संवाद बनाये रखने, ग्रामीण आयोजनों में युवाओं को आगे लाने और समाज सेवा से लेकर अंतिम व्यक्ति तक शासकीय सेवाओं योजनाओं को ले जाने में भी मितान क्लब योजना सहायक सिद्ध हो रही है. ग्रामीण अंचल के युवाओं में मितान क्लबों में अधिक सक्रीयता देखी जा रही है. खेल-कूद से लेकर सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में युवाओं को नेतृत्व मिल रहा है. युवाओं को अवसर मिलने से उनके बौद्धिक और व्यावहारिक ज्ञान में भी निरंतर विकास हो रहा है. छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में भागीदारी की बात हो, स्वास्थ्य-शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात हो या फिर शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार की, युवा सक्रीयता के साथ इन कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं.

जनसंपर्क के दौरान विकास उपाध्याय को मिल रहा जनता से प्यार, आशीर्वाद, स्नेह एवं सुझाव

रायपुर. संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ग्रीष्म ऋतु के नौतप्पा में आम लोगों से मिलने उनके निवास पहुँचकर उनसे हाल-चाल एवं वार्ड के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही आमजनों की परेशानियों का त्वरित समाधान भी कर रहे हैं। आज विधायक विकास उपाध्याय ठक्कर बापा वार्ड क्र.17 के तुलसी नगर स्थित दुर्गा मैदान में लोगों से मिलने पहुँचे जहाँ ठक्क्र बापा वार्ड के लगभग सभी लोगों ने विधायक से चर्चा की एवं विधायक ने वहाँ उपस्थित जनों से निर्माणाधीन कार्यों के बारे में पूछपरख भी की। तत्पश्चात् वे दानवीर भामाशाह वार्ड क्र.26 के गुढ़ियारी स्थित शुक्रवारी बाजार पहुँचकर लोगों से मिले एवं डोर-टू-डोर जनसंपर्क भी किया। लोगों ने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में विधायक को बताया कि हमारे क्षेत्र में अब ज्यादा समस्या नहीं है, और यदि हुई तो उसका निराकरण हमारे विधायक तुरंत ही कर देंगे। विधायक विकास उपाध्याय लगातार अपने क्षेत्र में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करने प्रयासरत् हैं चाहे बरसात का समय हो या फिर वर्तमान ग्रीष्म में भरे नौतप्पे का समय, विधायक अपने क्षेत्रवासियों के हित में निरन्तर विकास कार्य के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। आज विधायक विकास उपाध्याय के साथ पार्षद डॉ. अन्नू राम साहू, दिनानाथ शर्मा, सुन्दर लाल जोगी, तोरण साहू, अनिल बर्गे, सुरूज बाई गेन्दरे, कुतुब अली, बल्ली भैय्या, रेखा, कौशल्या, रूकमणी, ललिता, लीलू, पार्वती, खुशबु, शीला, माधुरी, गीता, सौमिल, सुनीता, दिलीप, जानकी, लक्ष्मी, रचना सहित काफी संख्या में महिलायें एवं आमजन सम्मिलित हुए।

युवाओं को मिला बड़ा संबलः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरूआत की

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो गई है. मुख्यमंत्री ने इस महत्वकांक्षी योजना की शुरूआत करते हुए कहा कि युवा हमेशा बेरोजगार न रहें इसके लिए उनके रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गयी है. ताकि बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेने वाले युवा प्रशिक्षण हासिल कर आने वाले समय में रोजगार भी हासिल कर सकें. मुख्यमंत्री ने योजना की शुरूआत के साथ ही चार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी जारी किया. मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले ये चार युवाओं ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते से इनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी. रायपुर जिले की रहने वाली बीएड की छात्रा पूजा चंद्रवंशी, रायपुर के मोवा में रहने वाली मुक्तेश्वरी, रायपुर के गुढ़ियारी में रहने वाले कुणाल साहू और रायपुर के ही कृष्णा नगर के रहने वाले दीपक निषाद को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता का चेक सौंपा. सभी युवाओं ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते से मिले पैसों से वो नई किताबें खरीद पाएंगे और अपने सपनों को पूरा करने के और नजदीक पहुंच पाएंगे.

बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपए का भुगतान सीधे हितग्राही के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाते का खाता नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी. बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी. योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा. यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा. किसी भी स्थिति में ये अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी. संबंधित पंचायत व निकाय नियमित रूप से हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या नहीं. जांच में अपात्र होने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा एवं इसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड की जाएगी. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को यदि किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो इसकी जानकारी हितग्राही को स्वयं पोर्टल में अपलोड करनी होगी. इस संबंध में जानकारी नहीं देने पर संबंधित निकाय या पंचायत को इसकी जानकारी अन्य माध्यम से प्राप्त होती है तो हितग्राही का भत्ता तत्काल बंद करने की जानकारी की प्रविष्टि पोर्टल में करेंगे और संबंधित हितग्राही के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

ये है शर्तें

बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरुरी है. योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले साल के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12 वीं कक्षा पास हो. साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो साल पुराना हो. आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो. पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो.

परिवार के एक सदस्य को मिलेगा भत्ता

बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा. ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो. उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा. उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो. आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा. यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा. पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे. साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे. साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे.

ऐसे करें आवेदन

बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रति वर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा. बेरोजगारी भत्ता लेने के इच्छुक आवेदकों को https://berojgaribhatta-cg-nic-in/ में ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इस वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा. रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी. ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा. आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है. ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके. विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा. सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी. डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी.

ऑनलाइन शिकायत और अपील

बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करना होगा. आवेदक के अपील का निराकरण कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी 15 दिन के अंदर करेंगे और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जाएगा. यदि कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है. इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा. इस निर्णय की जानकारी को भी पोर्टल में अपलोड किया जाएगा. शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा

योजना अंतर्गत जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन्हें एक वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा. कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद आवेदक को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी. आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. यदि आवेदक प्रशिक्षण लेने से इंकार करते है या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते है तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा.

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के 5 कारण, कैसे फेल हुई BJP की रणनीति?

कर्नाटक में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की. कर्नाटक के नतीजों के साथ-साथ अब रिजल्ट पर विश्लेषण भी शुरू हो गया है. कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के कारणों पर मंथन जारी है. आइए जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पांच बड़े कारण क्या रहे? कर्नाटक की जीत का असर इसी साल होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा. कर्नाटक का किला फतह करने के बाद कांग्रेस अब आगामी चुनावों में और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. कर्नाटक के नतीजों के बाद अब रिजल्ट पर विश्लेषण हो रहा है.

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है. आइए जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पांच बड़े कारण क्या रहे?

1. करप्शन, क्राइम और महंगाई के मुद्दे पर फोकस

कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर-शोर से उछाला. भाजपा की बोम्मई सरकार में कथित भ्रष्टाचार को निशाना बनाते हुए उसने '40 परसेंट की सरकार' का अभियान चलाया. चुनावी रैलियों में भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के अन्य नेता लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रहे. साथ ही कांग्रेस ने कर्नाटक के क्राइम पर भी फोकस बनाए रखा. क्राइम-करप्शन से जुड़े सवालों को कांग्रेस लगातार चुनावी मुद्दे के रूप में उठाती रही. इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव के दौरान महंगाई के मुद्दे को भी खूब उठाया. वोटिंग के दिन कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने वोटिंग से पहले गैस सिलेंडर की कीमत देखने की अपील की. जगह-जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की पूजा की. ये सब वैसे मसले हैं, जिससे हर किसी का सीधा संबंध होता है. आम जनों की आवाज बनने का असर आज कर्नाटक में कांग्रेस को जीत के रूप में मिली है.

2. पुरानी पेंशन, फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता जैसे पांच लुभावनी वायदे

कांग्रेस नेता ने कर्नाटक चुनाव के लिए पांच वायदे किए. जिनमें पुरानी पेंशन बहाल करने, 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने, 10 किलो अनाज मुफ्त देने, बेरोजगारी भत्ता देने और परिवार चलाने वाली महिला मुखिया को आर्थिक मदद की बात कही गई. ये सभी ऐसी घोषणाएं हैं, जिनसे अधिकांश लोगों का जुड़ाव है. इन लोक लुभावनी का वायदों को कर्नाटक की जनता पर असर पड़ा.

3. सही चुनावी प्रबंधन, आक्रमक प्रचार

कर्नाटक के लिए इस बार कांग्रेस ने चुनावी प्रबंधन काफी तगड़ी की थी. पार्टी के तेज-तर्रार नेता रणदीप सिंह सुरेजवाला को चुनाव से काफी पहले कर्नाटक का प्रभारी बनाकर भेज दिया था. जहां उन्होंने बेंगलुरु सहित अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट किया. कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व सीएम सिद्धारमैया के साथ मिलकर उन्होंने चुनावी प्रबंधन की पूरी बागडोर संभाली. इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा के कई बागी नेताओं को भी अपने पाले में किया. साथ ही कांग्रेस की एकता को बनाए रखा.

4. भारत जोड़ो यात्रा और पार्टी आलाकमान का प्रचार में जान लगा देना

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का भी बड़ा असर रहा. इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनकी टीम कर्नाटक के सात जिलों की 51 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी थी. इन 51 विधानसभा सीटों में से 37 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है,जेडीएस 9 और बीजेपी सिर्फ 4 पर आगे है. भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित अन्य नेता कर्नाटक में धुआंधार प्रचार करते नजर आए. जिसका असर आज नतीजे के रूप में देखने को मिल रहा है.

कर्नाटक की जीत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में जो माहौल दिखा था आज उसी का नतीजा कर्नाटक के चुनाव परिणाम में स्पष्ट दिख रहा है.

कर्नाटक के नतीजों पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने शानदार कैंपेन किया. कर्नाटक ने सांप्रदायिक राजनीति को नकार कर विकास की राजनीति को चुना है. आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी इसकी पुनरावृत्ति होगी.

5. बजरंग दल पर बैन लगाने का आश्वासन, बाद में फिर यू-टन

कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की घोषणा की. कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आते ही यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया. पीएम मोदी ने इसे भगवान बजरंग बली का अपमान करार दिया और इसके बाद बीजेपी की ओर से इसे प्रमुख मुद्दा बनाया गया. तिम दिनों में चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बजरंग बली के इर्द-गिर्द बना रहा.

भाजपा द्वारा इस बजरंग दल के मुद्दे को लपकने के बाद पहले तो कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की. पार्टी ने साफ कहा कि बजरंग बली हमारे आराध्य है. बात बजरंग दल पर बैन लगाने की हो रही है. लेकिन इसके बाद भाजपा द्वारा बजरंग बली के मुद्दे को उठाने रहने पर कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने यू-टर्न लेते हुए कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो जगह-जगह हनुमान जी की मंदिर बनवाएंगी. इससे भाजपा का बजरंग बली दांव भी फेल हो गया.

बृजमोहन ने राजधानी में ही खोली सरकार के गोधन न्याय योजना की पोल

रायपुर. वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की राजधानी रायपुर में ही पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने गोकुल नगर (मठपुरैना) एवं फुंडहर स्थित गौठान का निरीक्षण किया। इस दौरान यहा को जा रही गड़बड़ियां,अनियमितता उजागर हुई। फुंडहर में तो श्मशान घाट में ही गौठान का संचालन होना पाया गया।

बृजमोहन दोपहर को मठपुरैना गोकुल नगर स्थित गोधन न्याय योजना के गोबर खरीदी केंद्र पहुंचे

यहा पर एक भी कर्मचारी नही था। यहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के कुछ टाके खाली पड़ी थी। कुछ में मिट्टी गोबर और कीचड़ भरा हुआ था। यहां चारों तरफ गंदगी पसरी हुई थी। पूरा स्थल उजाड़ पड़ा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन समूह बनाए गए थे पर भुगतान नहीं होने के कारण वे छोड़कर चले गए। अभी चौथी समिति का कोई अता पता नही है। जो यहा का कामकाज देखते है वो अपनी डेयरी का गोबर लाते है मिट्टी मिलाते है और वर्मा कंपोस्ट के नाम पर नकली खाद बनाकर सरकार को दे देते है। बृजमोहन ने बताया कि गोकुल नगर में जिस स्थान पर गौठान का बोर्ड लगा है असल में वो निजी परिक्षेत्र हैं। यहां गौठान का संचालन सरकार या कोई स्थानीय समिति नहीं करती।

फुंडहर स्थित गौठान निरीक्षण के दौरान पाया कि कोई स्थानीय ग्राम की समिति इसका संचालन नही करती। दलदल सिवनी के किसी विक्रांत शर्मा नाम के ठेकेदार अब तक यहा का काम देखते थे पर अब अन्य समिति देख रही है। पूछताछ में पता चला कि कुछ गायों को आनन फानन में यहां लाया गया है। कई गाय भी बीमारी की हालत में है। स्वच्छता की कमी के साथ साथ उनके खाने के लिए पर्याप्त चारा भी नहीं है। साथ ही बताया गया कि तीन महीने से यहां पर गोबर को खरीदी नही हुई है। यहां बताया गया कि गांव वालों को गौठान में घुसने नहीं दिया जाता भीतर क्या कुछ हो रहा है उनसे छुपाया जाता है। निरीक्षण के दौरान गौठान के भीतर कुछ कब्र दिखाई पड़ी। पूछताछ पर ग्रामीणों ने बताया कि यह गौठान श्मशान घाट की जमीन पर बनाया गया है जो की सुप्रीम कोर्ट के आदेश कि श्मशान घाट की जमीन पर अन्य उपयोग नहीं हो सकता का उल्लंघन है।

इस संबंध में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार राजधानी रायपुर के गौठानों के निरीक्षण में हमने भारी अनियमितता पाई है। साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि यह पूरी योजना भ्रष्टाचार के मकसद से बनाई गई है। जिसमें केंद्रीय योजनाओं के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। इस पूरी योजना में 13 सौ करोड़ रुपए का घोटाला स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है।

बृजमोहन ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी सरकार है। अभी तो भाजपा न गौठान का घोटाला उजागर किया है, आने वाले समय में शराब घोटाला, रेत घोटाला,जमीन घोटाला जंगल,नौकरी घोटाला उजागर कर छत्तीसगढ़ की लुटेरी सरकार को बेनकाब करेगी। उन्होंने कहा कि गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाली इस कांग्रेस सरकार की रवानगी अब तय है। रायपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक नंदे साहू वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष तिवारी,जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल,सत्यम दुआ,रमेश ठाकुर, सालिक सिंह ठाकुर नीलेश शुक्ला, जितेंद्र धुरंधर,मनोज मिश्रा, चक्रधारी जगत सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

जियोमार्ट पर मंदी का साया ! छटनी की तैयारी पूरी

पिछले कुछ दिनों से ई-कॉमर्स साइट्स के कारोबार में मंदी है, जिसके चलते कई कंपनियों ने छंटनी का फैसला किया है. देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली जियोमार्ट ने लागत में कमी के हिसाब से 15,000 कर्मचारियों में से दो-तिहाई कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है. मुकेश अंबानी के जियो मार्ट के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी है.

पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनलाइन होलसेल फॉर्मेट जियो मार्ट ने प्राइस वॉर शुरू किया था. हाल ही में मुकेश अंबानी के जियो मार्ट ने मेट्रो कैश एंड कैरी को खरीदने के बाद अपना कारोबार समेटने के कारण 1000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की है. मुकेश अंबानी की जियोमार्ट में फिलहाल 15,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, आने वाले हफ्तों में दो तिहाई कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो मार्ट ने 1000 ग्राउंड स्टाफ और 500 कॉर्पोरेट ऑफिस स्टाफ से इस्तीफा देने को कहा है.

Reliance Industries की सहायक कंपनी Jiomart के परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान के मुताबिक, आने वाले हफ्तों में हजारों कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है.

इस बारे में एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि रिलायंस ने अपने सेल्स और मार्केटिंग विभाग के कई कर्मचारियों की तय सैलरी घटाकर उन्हें वेरिएबल पे स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर दिया है. रिलायंस का बिजनेस टू बिजनेस फॉर्मेट किराना स्टोर्स के लिए पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की जगह ले रहा है.

मेट्रो कैश एंड कैरी द्वारा 3500 से अधिक स्थायी कार्यबल को अवशोषित करने के बाद रिलायंस के बैक-एंड और ऑनलाइन बिक्री संचालन ने कई पदों पर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जियो मार्ट लागत में कटौती करने के लिए छंटनी कर रहा है.

इन शेयर्स ने निवेशकों को किया मालामाल, 352 फीसदी मिला रिटर्न

1 मार्च 2023 को समाप्त चौथी तिमाही के दौरान बाजार में नौ कंपनियों के शेयर कुछ इस तरह रहे हैं. जिन्होंने मार्च तिमाही के दौरान प्रॉफिट में साल-दर-साल 100% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है. कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इन सभी नौ कंपनियों ने एक साल में अपने निवेशकों को शानदार मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है. आइए जानते हैं इन सभी शेयरों के बारे में.

अपार इंडस्ट्रीज

अपार इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर में साल-दर-साल आधार पर 194 फीसदी की मुनाफा वृद्धि देखी गई है. अपार इंडस्ट्रीज के शेयर के रिटर्न की बात करें तो एक साल में 352 फीसदी का रिटर्न देखने को मिला है.

सोम डिस्टिलरीज

अगर हम सोम डिस्टिलरीज ब्रेवरीज एंड वाइनरीज स्टॉक (सोम डिस्टिलरीज शेयर प्राइस) के साल-दर-साल प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो यह करीब 148 फीसदी रही है. वहीं, एक साल में यहां निवेशकों को 193 फीसदी का रिटर्न मिला है.

न्यूलैंड प्रयोगशालाओं

न्यूलैंड लेबोरेटरीज (न्यूलैंड लेबोरेटरीज शेयर प्राइस) के स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए सालाना आधार पर अपने लाभ में 288% की वृद्धि की है. न्यूलैंड लैब के शेयर से निवेशकों को एक साल में करीब 169 फीसदी का अच्छा मुनाफा भी हुआ है.

तिलकनगर उद्योग

तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयर ने अपने निवेशकों को एक साल में करीब 168 फीसदी का दमदार रिटर्न दिया है. प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी कंपनी अच्छी रही है. इसने साल-दर-साल आधार पर लगभग 154% की लाभ वृद्धि दिखाई है.

सफारी उद्योग

ट्रैवल बैग और बैग पैक जैसे उत्पाद बनाने वाली सफारी इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस ने अपने निवेशकों को एक साल में 167 फीसदी का रिटर्न दिया है. प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है. जहां कंपनी ने सालाना आधार पर करीब 1488 फीसदी प्रॉफिट ग्रोथ दी है.

अनंत राज

अनंत राज शेयर की कीमत कंपनी के शेयर ने सालाना आधार पर 120% का मुनाफा दिखाया है. एक साल में रिटर्न के लिहाज से भी शेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है. जहां उन्होंने करीब 149% का रिटर्न दिया है.

प्रिकोल

प्रिकोल स्टॉक ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है. कंपनी ने एक साल में करीब 117 फीसदी का रिटर्न दिया है. प्रॉफिट ग्रोथ के लिहाज से यह साल-दर-साल आधार पर करीब 127 फीसदी रही है.

जिंदल साव

जिंदल ने प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में सालाना आधार पर करीब 142 फीसदी की ग्रोथ दिखाई है. निवेशकों को एक साल के आधार पर मिला रिटर्न देखें तो यह करीब 115 फीसदी रहा है.

रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर

लाभ वृद्धि के मामले में रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर शेयर प्राइस के शेयर में वार्षिक आधार पर लगभग 339% की वृद्धि हुई है. रिटर्न के मामले में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. एक साल में अपने निवेशकों को 102 फीसदी का रिटर्न दिया है.

लॉन्च हो गया सबसे ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर!

कीमत है कम, चार्ज होगा जल्दी

आज इंडियन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में एक और नए प्लेयर की आधिकारिक एंट्री हो गई है. बेंगलुरु बेस्ड Simple Energy ने आज अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple One को लॉन्च किया है. स्पोर्टी लुक और दमदार बैटरी पैक से सजे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर कंपनी का दावा है कि ये सेग्मेंट में सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज देता है. इसके अलावा ये सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इसे कुल 6 रंगों में पेश किया गया है, जिसमें से 4 रेगुलर कलर और 2 स्पेशल कलर शामिल हैं. इसकी शुरुआती कीमत 1.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) तय की गई है.

लेकिन ये इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खासियत नहीं है. इसकी खासियत कुछ ऐसी है कि बाजार में अपना राज किए बैठे OLA S1, Chetak, Vida, Tvs iCube और ।जीमत जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों के सामने अब मुश्किल खड़ी होने वाली है. सिंपल वन की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी रेंज होगी. कंपनी ने दावा किया है कि ये सिंगल चार्ज में 212 किलोमीटर की रेंज देगा. स्कूटर को खरीदने के लिए इसे आप सिंपल एनर्जी की वेबसाइट पर आसानी से ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं.

कितनी है कीमत

सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1.45 लाख रुपये से शुरू होती है, जो 1.58 लाख रुपये तक जाती है. ये सभी कीमतें, एक्स-शोरूम बेंगलुरु हैं. 750 वॉट के पोर्टेबल चार्जर के लिए ग्राहकों को 13,000 रुपये अतिरिक्त देना होगा. कीमतें 1 जून, 2023 से लागू होने वाली संशोधित FAME II सब्सिडी योजना के अनुरूप हैं. कंपनी का दावा है कि पिछले 18 महीनों में सिंपल वन के 1 लाख से अधिक प्री बुकिंग मिल चुकी है. अब, आधिकारिक लॉन्च के साथ, कंपनी की योजना ग्राहकों को चरणबद्ध तरीके से डिलीवरी की सुविधा देने की है, जिसकी शुरुआत 6 जून, 2023 को बेंगलुरु से होगी. सिंपल एनर्जी ने पहली बार अगस्त 2021 में अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर से पर्दा उठाया था. इस मॉडल को उत्पादन में लाने के लिए कंपनी को डेढ़ साल से ज्यादा का समय लगा है.

क्या हैं फीचर्स

सिंपल वन में कंपनी ने ब्लूटूथ, एलईडी लाइटिंग, एंड्रॉयड ओएस जैसे आम फीचर्स तो दिए ही हैं. इसके साथ ही क्लाउट कनेक्टिविटी और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे शानदार फीचर्स से भी इसे लैस किया गया है जो अभी तक केवल प्रीमियम कारों में ही देखने को मिलते थे.

इसके साथ ही स्कूटर में कई राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं जैसे इको, डैश, राइड और सोनिक. स्कूटर में 30 लीटर का स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है. सिंपल वन अब फिक्स्ड और रिमूवेबल (पोर्टेबल) बैटरी से लैस है, जो आईडीसी में 212 किलोमीटर की शानदार रेंज देता है, जो इसे भारत में सबसे ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है. इसके अलावा, सिंपल वन अपने सेगमेंट में सबसे फास्ट इलेक्ट्रिक टूव्हीलर है. ये इलेक्ट्रिक स्कूटर महज 2.77 सेकंड में ही 0-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है.

सिंपल वन में 5kWh की लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये बैटरी सिंगल चार्ज में 212 किलोमीटर (6 प्रतिशत SOC के साथ) तक का रेंज देगी. यह बैटरी दो पैक दो अलग-अलग रूप में आती है, एक फिक्स्ड और दूसरा रिमूवेबल. यहां पर SOC का अर्थ है कि, जब बैटरी में 6% पावर बचा रहता है यानी कि 100% बैटरी के इस्तेमाल पर ये स्कूटर तकरीबन 220 से 225 किलोमीटर तक का रेंज दे सकती है.

लॉन्च होने से पहले मारुति सुजुकी जिम्नी की हुई बंपर एडवांस बुकिंग

‘मारुति सुजुकी जिम्नी जाहिर तौर पर इस साल की बहुप्रतीक्षित न्यू कार लॉन्च में से एक है. यह लाइफस्टाइल, ऑफ-रोड एसयूवी जून 2023 के पहले हफ्ते में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारुति जिम्नी 7 जून को लॉन्च होने वाली है. इसके बाजार में लॉन्च से पहले कार निर्माता ने इसके फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशन और माइलेज के आंकड़ों का खुलासा किया है. नई 5-डोर मारुति जिम्नी को पावर देने वाला 1-5 लीटर K15B नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 5-स्पीड मैनुअल या 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आ सकता है.’

मारुति जिम्नी वेरिएंट, फीचर्स

मारुति सुजुकी जिम्नी जीटा और अल्फा जैसे केवल दो वेरिएंट में आएगी. एंट्री-लेवल जेटा ट्रिम में स्टील व्हील्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर्स, 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 7.0-इंच टचस्क्रीन स्मार्टप्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, पावर विंडो, कलर एमआईडी जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसमें डिस्प्ले, सीटबेल्ट प्रीटेंशनर, रिवर्सिंग कैमरा, ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

जबकि इसके टॉप मॉडल में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 9.0 इंच का टचस्क्रीन स्मार्टप्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कामिस साउंड सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, फॉग लैंप, एलईडी हेडलैंप, हेडलैंप वाशर, ऑटो हेडलैंप, अलॉय व्हील और बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेगा. सुरक्षा के लिए जिम्नी एसयूवी में छह एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल व ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल दिया गया है. यह एसयूवी 36 डिग्री अप्रोच एंगल, 50 डिग्री डिपार्चर एंगल, 24 डिग्री ब्रेक-ओवर एंगल के साथ आता है.

महेंद्रा थार से होगा मुकाबला

मारुति जिम्नी के थ्री-डोर वर्जन का प्रोडक्शन कंपनी पहले से करती आ रही है, जिसे दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है. ऐसा पहली बार है जब 5-डोर मॉडल को बाजार में उतारा जाएगा. लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला महेंद्रा थार से होगा, जो कि फिलहाल थ्री-डोर वर्जन में ही उपलब्ध है. महिंद्रा भी अपने थार को 5-डोर वर्जन को पेश करने जा रही है. हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. जहां तक कीमत की बात है तो कंपनी इसे 10 से 12 लाख रुपये के बीच लॉन्च कर सकती है.

Motorola ने भारत में लॉन्च किया Edge 40

धमाकेदार फीचर्स के साथ मिलेगा डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर

मोटोरोला ने मिड रेंज सेंगमेंट का स्मार्टफोन, Motorola Edge 40 को भारत में लॉन्च किया है. इस फोन में 5000 एमएएच की बैटरी, मीडियाटेक डायमेनसिटी 8020 प्रोसेसर और 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है. फोन की सेल आज से शुरू हो गई. जानिए इसकी कीमत.

Motorola Edge 40 कीमत और उपलब्धता

मोटोरोला के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 29,999 रुपये है. लेकिन 2,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ इस हैंडसेट को 27,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. फ्लिपकार्ट हैंडसेट के साथ स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रही है. अगर आप चाहें तो फोन को बड़े बैंकों के कार्ड के साथ नो-कॉस्ट ईएमआई पर खरीद सकते हैं. नए एज 40 प्रो की बिक्री 30 मई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. यह फोन मोटोरोला की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और दूसरे रिटेल स्टोर के जरिए देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. फोन को नेबुला ग्रीन और इकलिप्स ब्लैक कलर में पेश किया गया है.

मिलेंगे ये ऑफर्स

अगर आप नो-कॉस्ट EMI का विकल्प चुनते हैं तो आप कुछ बैंक कार्ड का उपयोग 5000 रुपये प्रतिमाह की कीमत पर इसे अपना बना सकते हैं.

इसके अलावा आप 2,000 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं. ये फोन को तीन कलर वेरिएंट- एक्लिप्स ब्लैक, लूनर ब्लू और नेबुला ग्रीन में पेश किया गया है. ग्रीन और ब्लैक वेरिएंट वीगन लेदरबैक फिनिश के साथ आते हैं, जबकि ब्लू वेरिएंट में मैट एक्रेलिक रियर पैनल मिलता है.

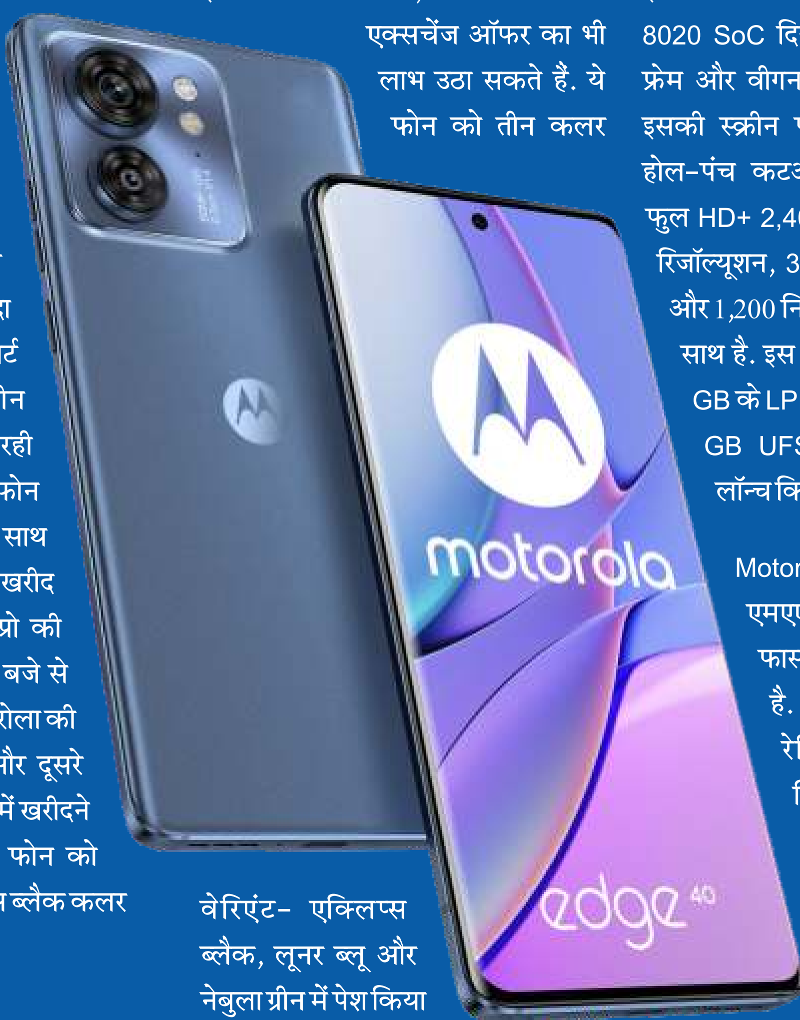

Motorola Edge 40 के स्पेसिफिकेशंस

इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8020 SoC दिया गया है. इसका मेटल फ्रेम और वीगन लेदर में बैक पैनल है. इसकी स्क्रीन पर फ्रंट कैमरा के लिए होल-पंच कटआउट है. इसका डिस्प्ले फुल HD+ 2,400 x 1,080 पिक्सल के रिजॉल्यूशन, 360 Hz टच सैंपलिंग रेट और 1,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ है. इस स्मार्टफोन को यूरोप में 8 GB के LPDDR4X RAM और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है.

Motorola Edge 40 में 4400 एमएएच की बैटरी 68 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है. ये स्मार्टफोन IP68 की रेटिंग के साथ आता है जिसका मतलब है कि इसे धूल, मिट्टी और पानी में कुछ नहीं होगा. मोटोरोला का दावा है कि यह IP68 रेटिंग वाला सबसे स्लिम 5G स्मार्टफोन है. इसमें 6.55 इंच pOLED डिस्प्ले है. कंपनी ने एक ट्वीट में बताया कि स्मार्टफोन 30 मिनट तक पानी में सर्वाइव कर सकता है.

नोकिया का 'सस्ता' स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ कीमत होगी 10 हजार से कम

नोकिया के नए फोन का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. कंपनी ने इंडियन यूजर्स के लिए अपने नए हैंडसेट- Nokia C32 को लॉन्च कर दिया है. यह एंट्री लेवल स्मार्टफोन दो वेरिएंट 4 जीबी़ 64 जीबी और 4 जीबी़ 128जीबी में आता है. इसके 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है. वहीं, इसके 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट के लिए आपको 9,499 रुपये खर्च करने होंगे. इस फोन को आप नोकिया इंडिया के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं. नोकिया के इस लेटेस्ट फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी के अलावा कई जबर्दस्त फीचर मिलेंगे.

Nokia C32 की भारत में कीमत और उपलब्धता

भारत में Nokia C32 की कीमत 4GB + 64GB वेरिएंट के लिए 8999 रुपये है. इसके 4GB + 128GB वेरिएंट को 9499 रुपये में लॉन्च किया गया है. नोकिया इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर यह फोन खरीदारी के लिए उपलब्ध है. कस्टमर नो-कॉस्ट ईएमआई का लाभ भी ले सकते हैं, जो 1584 रुपये प्रति माह से शुरू होती है. इसे 'बीच पिंक', 'चारकोल' और 'मिंट' कलर्स में लाया गया है.

Nokia C32 स्पेसिफिकेशन्स

नोकिया सी32 स्मार्टफोन में 6.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो एचडी़ (720×1600 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है. डिवाइस का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है. फोन में डिस्प्ले पर वॉटरड्रॉप नॉच दी गई है जिसमें सेल्फी कैमरा मिलता है. हैंडसेट में 1.6 गीगाहर्ट्ज न्दपेवबै ब9863। प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 4 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है. नोकिया के इस फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. डिवाइस 3 जीबी वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आती है.

कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50MP का मेन लेंस कैमरा और 2MP का सेकेंडरी लेंस कैमरा होगा. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. पावर बैकअप के लिए 10W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी मिलेगी. सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और साथ में IP52 रेटिंग दी गई है.

ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करता है. कंपनी इस फोन को दो साल तक क्वॉटर्ली सिक्योरिटी अपडेट देती रहेगी. फेस अनलॉक फीचर वाले इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए 4G, Wi-Fi 802-11 b/g/n/ac, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं.

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के नये आयाम

- **महिला सम्मेलन पर विशेष**
- **महिलाओं को सशक्त बनाना**

रायपुर. महिलाओं को सशक्त बनाना है तो स्वास्थ्य-शिक्षा के साथ-साथ उन्हें अधिकार और आगे बढ़ने के सुरक्षित अवसर देने होंगे. उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नये रास्ते बनाना भी जरूरी है. इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ उनकी सृजन क्षमता को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है. महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ा यह दृष्टिकोण उनके लिए विकास के नये आयाम खोलता है.

महिलाओं को सशक्त बनाना

नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है. राज्य शासन द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण वर्ष 2016 से 2018 के बीच 159 एमएमआर वाले छत्तीसगढ़ का एमएमआर अब घटकर 137 पर पहुंच गया है. कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है. छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपाषण अभियान से अब तक 2 लाख 65 हजार बच्चे कुपोषण मुक्त तथा एक लाख 50 लाख महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं. एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए (आयरन फोलिक एसिड) सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है.

बिहान से जुड़ी है ढाई लाख महिला समूह

छत्तीसगढ़ में महिलाओं की प्रगति के लिए अपनाई गई नीतियों और उनके संरक्षण का ही परिणाम है, कि यहां वनोपज के कारोबार से 50 हजार से अधिक महिलाएं जुड़कर छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहीं हैं, वहीं जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्रामीण महिलाएं, ग्राम सभा सदस्यों के रूप में खुद के लिए नीतियां भी तैयार कर रही हैं. प्रदेश में करीब 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए जा चुके हैं, जहां महिलाओं को अच्छा रोजगार और अच्छी आय मिल रही है. महिलाओं को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने लगभग चार हजार बहनें बीसी सखी के रूप में चलते-फिरते बैंक के रूप में बैंकिंग सुविधाएं दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से करीब 27 लाख गरीब परिवारों की महिलाएं 02 लाख 54 हजार स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं.

महिलाओं के श्रम से चमका डेनेक्स

बस्तर के घने जंगलों में नक्सलियों से साहस के साथ मोर्चा ले रहीं बस्तर की दंतेश्वरी फाइटर्स अपने पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. गोधन न्याय योजना के तहत गांव-गांव में बनाए गए गौठानों में लगभग 45 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है. ये महिलाएं गौठानों में आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से न सिर्फ सशक्त बन रही हैं, बल्कि अपने परिवारों के लिए भी संबल बन गई हैं. गोठानों बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी-मार्ट स्टोर जैसी नई अवधारणा से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है. महिलाओं द्वारा तैयार

सामाग्री को बाजार मिल रहा हैं. बस्तर के आदिवासी जिले दंतेवाड़ा की डेनेक्स गारमेंट फैक्टरी में काम कर रही महिलाओं ने देश-विदेश में डेनेक्स ब्रांड को लोकप्रिय बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है. बीजापुर की महिलाओं का महुआ लड्डु, कोंडागांव का तिखुर शेक, सुकमा की ईमली-कैंडी और नारायणपुर का फूल झाड़ू भी प्रसिद्ध हो चुका है.

महिला कोष का बजट 25 करोड

महिला कोष से ऋण लेकर आर्थिक गतिविधि जुड़ी महिला समूहों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समूह द्वारा लिए गए पुराने 12 करोड़ रूपये के ऋण माफ कर दिये हैं. साथ ही ऋण लेने की सीमा को भी दो से चार गुना तक बढ़ा दिया है. महिला कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋण सीमा में भी दोगुनी वृद्धि की गई है. महिला कोष के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है. पूर्व वर्षों में महिला कोष को एक या दो करोड़ वार्षिक आबंटन उपलब्ध होता था मगर वर्ष 2023-24 में 25 करोड़ रूपए का वार्षिक बजट उपलब्ध कराया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा 10 हजार 500 से अधिक महिलाओं के लिए पिछले 5 सालों में सर्वाधिक 10 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक ऋण राशि स्वीकृत की गई है. नई कौशल्या समृद्धि योजना शुरू करने की योजना है, इसमें महिलाओं को व्यवसाय के लिए आसान शर्तों पर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा. इसके लिए 25 करोड़ रूपए का बजट अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया है.

महिला उद्यमिता नीति

महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, राज्य का विकास उतनी ही तेजी से होगा, इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में महिलाओं की क्षमता को

एक नई ऊंचाई देने के लिए महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू कर दी गई है. इसमें महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ कई प्रकार की छूट का प्रावधान किया गया है. राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए 10 से 50 लाख रूपए ऋण के साथ विद्युत शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट, परिवहन अनुदान, मण्डी शुल्क से छूट, किराया अनुदान जैसे कई प्रावधान किये गए हैं. महिला स्व-सहायता समूहों और महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए भी 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं एक वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है, इससे उद्योग एवं व्यापार में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी.

राशन कार्ड और मकान महिलाओं के नाम पर

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भूमि और संपत्ति पंजीयन पर एक प्रतिशत की छूट दी जा रही है. राशन कार्ड और आवास आबंटन महिलाओं के नाम पर किए जा रहे है. सरकारी सेवाओं में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए भर्ती, पदोन्नति, दस्तावेजों की छानबीन के कार्यों के लिए बनाई गई समितियों में एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रखने की व्यवस्था बनाई गई है. लैंगिक अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक समिति बनाई गई है, जो इस मामले की जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही करने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं.

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

हर संभाग में कामकाजी हॉस्टल के साथ जिला मुख्यालयों में महिला हॉस्टल बनाए जाने की शुरूआत की गई है. थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क संचालित हैं,

जिससे महिलाएं मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा सकें. छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सहायता के लिए अभिव्यक्ति एप बनाया गया है. महिला हेल्पलाईन नम्बर 181 और सखी सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता और आश्रय भी प्रदान किया जा रहा है. अब तक 37 हजार 158 पीड़ित महिलाओं को सहायता और 13 हजार 750 महिलाओं को आश्रय दिया गया है. नवा बिहान योजना के माध्यम से घरेलू हिंसा के प्रकरणों में 4331 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है.

बढ़ा मान और बढ़ा मानदेय

राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य की देखभाल कर रहीं महिला कर्मियों के मानदेय में वृद्धि कर उनका सम्मान भी बढ़ाया है. इस साल बजट में प्रदेश के 46 हजार 660 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करते हुए अब इसे 06 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है. आंगनवाड़ी साहियकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रुपए से बढ़ाकर 05 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है. मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 07 हजार 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. मितानिन बहनों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रुपए प्रति माह की दर से मानदेय देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है, इससे प्रदेश की 72 हजार मितानिनों की पुरानी मांग पूरी हुई है. इसके साथ ही मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय को भी बढ़ाया गया है, जिससे बहुत सी ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी.

कन्या विवाह के लिए अब 50 हजार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामाजिक पृष्टिभूमि में महिलाओं और उनके परिवारों के मान-सम्मान का भी ध्यान रखते हुए कई निर्णय लिए हैं. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को भी अपने कार्यकाल में दो बार बढ़ाकर बेटियों के विवाह के लिए बड़ी राहत दी है. 2019 में यह राशि 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गई और अब बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है. निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है.

9 नए महिला महाविद्यालय

महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उन तक उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचाकर जागरूकता लाना भी आवश्यक है. इसे देखते हुए पिछले साल 2239 विधिक व महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया गया. इस वर्ष महिला जागृति शिविर मद के बजट में दोगुनी वृद्धि कर 4.85 करोड़ से बढ़ाकर 9.33 करोड़ किया गया. इसके साथ ही राज्य महिला आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारियों और कानूनों की जानकारी भी दी जा रही हैं. राज्य की 9 जिला मुख्यालयों में नए महिला महाविद्यालय की शुरूआत के साथ महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोले गए हैं.

रीनू ठाकुर,
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी. रायपुर.

झुग्गी बस्ती से निकलकर श्रमिकों के बच्चों ने बनायी अंतर्राष्ट्रीय पहचान

- भारतीय साफ्ट बाल टीम में राज्य के तीन युवा कर रहे हैं प्रतिनिधित्व
- अब मजदूर के बच्चे मजदूर नहीं रहेंगे, उन्हें भी छूना है आसमानः मुख्यमंत्री बघेल
- श्रमिक हित में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कर रही है काम

"कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों. कवि दुष्यंत कुमार की ये कविता आज छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है जो ऐसे समाज से आते हैं जो शायद ही कभी बड़े सपने देखते हों. ऐसे ही समाज और परिवार को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रमिक हितों में लगातार काम कर रहे हैं. विगत चार वर्षों से छत्तीसगढ़ में श्रमिक हितों में मुख्यमंत्री ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनका लाभ लेकर अब श्रमिकों के बच्चे भी आसमान छू रहे हैं. ऐसे ही श्रमिक परिवारों के तीन होनहार सितारे छत्तीसगढ़ के झुग्गी झोपड़ी से निकलकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं."

रायपुर के रहने वाले निखिल नायक, बीरू बाग और किशन महानंद रायपुर की झुग्गियों से निकलकर कनाडा और हांगकांग में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. ये तीनों पिछले चार वर्षों से इंडियन साफ्ट बाल टीम के सदस्य हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं. छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हुए इन तीनों ने अब तक सात गोल्ड मेडल हासिल किए हैं.

निखिल नायक के पिता विनोद नायक, बीरू बाग के पिता घनवर बाग और किशन महानंद के पिता भगवान दास दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं. चार साल पहले तक इनके मन में गलती से भी ये खयाल नहीं आता था कि ये अपने बच्चों को भी मजदूरी के अलावा कुछ और करते देख सकते हैं. लेकिन मुख्यमंत्री श्री बघेल ने असंगठिक श्रमिकों से वायदा किया था कि अब मजदूर के बच्चे मजदूर नहीं रहेंगे और इस वायदे को उन्होंने निभाया और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू कर उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण के द्वार खोले. इसी का परिणाम था कि ये तीन होनहार युवा कुछ अलग करने की दिशा में आगे बढ़े और आज रायपुर की तंग गलियों से निकलकर देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए मुख्यमंत्री ने इन होनहार खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 50-50 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है और इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.

मनोज सिंह, सहायक संचालक. रायपुर.

इन शेयरों ने निवेशकों को बनाया मालामाल, एक लाख के बने 1.33 करोड़, जानिए डिटेल

घरेलू ही नहीं विदेशी निवेशकों ने भी शेयर बाजार से अच्छी कमाई की है. पिछले 9 साल में कम से कम 44 शेयरों ने मल्टीबैगर रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल किया है. पिछले 9 सालों में भारत में विदेशी निवेश की बाढ़ सी आ गई है. इसके साथ ही घरेलू निवेशकों ने भी शेयर बाजार में जमकर निवेश किया है.

उभरते बाजारों में भारत का शेयर बाजार तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. शेयर बाजार के स्टार परफॉर्मर के विश्लेषण से पता चला है कि निफ्टी 50 इंडेक्स के 44 शेयरों ने इस दौरान 1000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है.

बजाज ग्रुप की दो फाइनेंस कंपनियों बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने 9 साल में शानदार रिटर्न दिया है. बजाज फाइनेंस ने 9 साल में निवेशक को 3280% का रिटर्न दिया है. बजाज फिनसर्व ने नौ वर्षों में निवेशकों को 1513% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.

अगर किसी व्यक्ति ने 9 साल पहले बजाज फाइनेंस के शेयरों में ₹1,00,000 का निवेश किया होता, तो उसकी राशि अब तक 3 करोड़ हो गई होती. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तानला प्लेटफॉर्म्स ने पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में निवेशकों को 11325 फीसदी का रिटर्न दिया है. वर्ष 2014 में Tanla Platforms के शेयर की कीमत 6 थी,

जो वर्ष 2023 में 3 अंकों तक पहुंच गई है.

यदि किसी व्यक्ति ने नौ साल पहले ₹1,00,000 के तनला प्लेटफॉर्म्स के शेयर खरीदे होते, तो उसे नौ साल पहले 16666 शेयर मिलते. अब Tanla Platforms के शेयर की कीमत 731 के स्तर पर है. इस हिसाब से 9 साल पहले तानला प्लेटफॉर्म्स में किया गया निवेश मिल्टिबैगर रिटर्न के साथ 1.21 करोड़ रुपये हो जाता.

निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. इनमें Mastec, Koforge, Tata Elxsi और Sonata Software जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने निवेशकों को एक हजार फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है.

छत्तीसगढ़ में सबका बढ़ता मान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस पर श्रमिकों का मान बढ़ाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में इन्हें देय राशि 50 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने की घोषणा की. साथ ही अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी.

> छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई न्याय योजनाओं से समाज के शोषित वंचित और गरीब तबकों का न केवल मान बढ़ा है बल्कि इन योजनाओं की बयार से बड़ी राहत मिल रही हैं. सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी है. स्वामी आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जैसी नवाचारी पहल से लोगों को आसानी से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रहीं हैं. बेरोजगारों को प्रतिमाह भत्ता मिलना प्रारंभ हो चुका है. इसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की भी चिंता करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि कर उनका मान बढ़ाया है.

इसी प्रकार श्रमिकों के लिए मासिक सीजन टिकट एमएसटी जारी किया जाएगा, इससे घर से रेल अथवा बस से कार्यस्थल तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी. यह कार्ड 50 किमी तक की यात्रा के लिए मान्य होगा. पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को नवीन आवास निर्माण अथवा क्रय के लिए 50 हजार रुपए का अनुदान और हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, पैर के घुटने की सर्जरी, कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अतिरिक्त भी 20 हजार रुपए का अनुदान निर्माणी श्रमिकों को मिलेगा.

छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 250 करोड़ रूपये का नवीन मद में प्रावधान किया है. बेरोजगारी भत्ता योजना के पात्र पाए गए 66 हजार 256 युवाओं के खाते में 16 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार करते हुए इसे नगर पंचायतों में भी लागू किया है. इस योजना में 4 लाख 99 हजार से अधिक लोगों के बैंक खाते में अब तक 476.62 करोड़ की राशि अंतरित की गई है.

सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की भी चिंता करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है. आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय वर्ष 2018 तक 2,500 रूपए प्रतिमाह था, जिसे बढ़ाकर 3,250 रूपए किया गया. वर्ष 2022-2023 में इसे बढ़ाकर 5,000 रूपए कर दिया गया. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय वर्ष 2018 तक 3,250 रूपए प्रतिमाह था, जिसे बढ़ाकर 4,500 रूपए किया गया. वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 7,500 रूपए किया गया. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय वर्ष 2018 तक 5,000 रूपए प्रतिमाह था, जिसे 6,500 रूपए किया गया. वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 हजार रूपए किया गया.

मध्यान्ह भोजन रसोईयों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 1,800 रूपए की गई है. स्कूल स्वच्छताकर्मियों का मानदेय 2,500 रूपए से बढ़ाकर 2,800 रूपए कर दिया गया है. मितानिनों को राज्य मद से 2,200 रूपए

प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार वृद्ध पेंशन, विधवा, निराश्रित पेंशन की राशि को 350 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए कर दिया गया है. स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और सदस्यों को 500 रूपये मानदेय प्रतिमाह मिलेगा.

ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है. सरकार ने ग्राम कोटवारों को दिए जाने वाले मानदेय की दरों में भी वृद्धि की है, जिसके अनुसार 2,250 के स्थान पर 3,000 रूपए, 3,375 के स्थान पर 4,500 रूपए, 4,050 के स्थान पर 5,500 रूपए और 4,500 के स्थान पर 6,000 रूपए किया गया है. होमगार्ड के जवानों का मानदेय न्यूनतम 6300 से अधिकतम 6420 रूपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी की गई है. ग्राम पटेलो का मानदेय 2000 रूपए से बढ़ाकर 3000 रूपए प्रतिमाह किया गया है.

जी.एस. केशरवानी, उप संचालक. रायपुर

बाजार में अचानक बढ़ी स्मार्टफोन की बिक्री, मार्केट में बरस रहे 2000 के नोट

गुलाबी नोट से धड़ाधड़ बिक रहे मोबाइल

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद देश भर के स्मार्टफोन खुदरा विक्रेताओं ने मोबाइल की बिक्री और पूछताछ में भारी उछाल दर्ज किया है। कुछ खुदरा विक्रेताओं ने मुख्य रूप से नकद लेनदेन के माध्यम से बिक्री में 10% -11% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं, कुछ रिटेलर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए 2000 रुपए के नोट से खरीदारी स्वीकार कर रहे हैं और डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इससे जुड़े पोस्टर भी दुकानों के बाहर लगाए जा रहे हैं। इस वजह से भी कैश की बिक्री में तेजी आई है। केंद्रीय बैंक ने 20 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी और जनता से 30 सितंबर तक बैंक शाखाओं में नोट जमा करने या बदलने का आग्रह किया था। खुदरा विक्रेताओं ने कहा कि घोषणा के बाद से, ग्राहकों से स्मार्टफोन खरीदने के बारे में पूछताछ की जा रही है। और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नोट्स का उपयोग कर।

दिल्ली में नकद भुगतान से मोबाइल की बिक्री 11 फीसदी बढ़ी

पश्चिमी दिल्ली के एक रिटेलर ने ईटी को बताया कि आरबीआई की घोषणा के बाद से हमने बिजनेस में करीब 10-11 फीसदी की ग्रोथ देखी है और यह ग्रोथ कैश ट्रांजेक्शन में है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ज्यादातर लेन-देन क्रेडिट कार्ड या बैंक फाइनेंसिंग के जरिए किया जाता है, लेकिन पिछले हफ्ते से हमारे काउंटरों पर कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है।

कर्नाटक में स्मार्टफोन की बिक्री के लिए विशेष ऑफर

कर्नाटक के चिकमगलूर में दो आउटलेट चलाने वाले एक स्मार्टफोन रिटेलर ने 2,000 रुपये के नोट स्वीकार करने और नए आईफोन मॉडल को खरीदने पर छूट देने वाले पोस्टर और फ्लायर्स लगाए हैं। पोस्टर में हाइलाइट किया गया है कि आईफोन 13 प्रो को खरीदने के लिए 2,000 रुपये के 32 नोटों की जरूरत है, जो आईफोन 14 प्रो के लिए 68 नोटों के साथ आता है और डिवाइस को ले जाता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लेन-देन अब नकद में हो रहा है। उन्होंने महंगे हैंडसेट पर 4,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट भी दिया।

कोलकाता में बिक्री पर बाजार का रुझान सकारात्मक है

कोलकाता के एक रिटेलर ने कहा कि आरबीआई की घोषणा के बाद बिक्री में तत्काल कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नोट एक्सचेंज दृष्टिकोण की समय सीमा के अनुसार बिक्री में तेजी आएगी। वहीं, त्योहारी सीजन को देखते हुए बिक्री में उछाल आने की संभावना है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, स्मार्टफोन शिपमेंट ने 2023 की पहली तिमाही में 19: की सबसे खराब गिरावट दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि यह गिरावट की लगातार तीसरी तिमाही थी। वहीं, आरबीआई के ताजा फैसले से स्मार्टफोन की बिक्री में तेजी आने की संभावना है और आंकड़ों में सुधार होगा.

धुम मचाने आ रहा Xiaomi का तगड़ा सेल्फी कैमरा फोन, 32MP+32MP Selfie कैमरे के साथ मिलेगा 1TB की स्टोरेज

Xiaomi अपने नए स्मार्टफोन Xiaomi Civi 3 को चीनी बाजार में 25 मई को यानी आज लॉन्च कर दिया है. शाओमी का ये फोन सेल्फी फोकस्ड होने वाला है. नए फोन में 6.55-इंच OLED डिस्प्ले है, जिसमें फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है. फोन मीडियाटेक के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है और इसमें 16GB तक रैम और 1TB तक का इंटरनल स्टोरेज मिलता है. फोटोग्राफी के लिए इसमें तीन रियर कैमरे और दो सेल्फी कैमरे मिलते हैं. कितनी है कीमत, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ.

Xiaomi CIVI 3 कीमत

यह शाओमी फोन तीन मैमोरी वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है जिनमें 12जीबी रैम, 256जीबी स्टोरेज, 12जीबी रैम, 512जीबी स्टोरेज तथा 16जीबी रैम, 1टीबी स्टोरेज शामिल है. इन तीनों वेरिएंट्स का प्राइस 2499 yuan, 2699 yuan और 2999 yuan है. यह कीमत इंडियन करंसी अनुसार 29000 रुपये, 31500 रुपये और 35,000 रुपये के करीब है.

Xiaomi Civi 3 में क्या होगा खास

Xiaomi Civi 3 को हाल ही में MIIT सर्टिफिकेशन डाटाबेस पर देखा गया था, जहां पता चला है कि इस फोन में 12GB RAM और 512GB स्टोरेज दी जाएगी. इसके अलावा Xiaomi और भी ज्यादा दमदार स्पेसिफिकेशंस के साथ एक वेरिएंट पेश करेगा, जिसमें 16GB RAM और 1TB स्टोरेज होगी. ब्रांड के लेटेस्ट पोस्टर में इसका खुलासा हुआ है. स्टोरेज की बात करें तो Civi 3 में LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिल सकती है. फोन में 8GB RAM के साथ 256GB और 12GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज भी दी जा सकती है.

दो सेल्फी कैमरे

Xiaomi CIVI 3 स्मार्टफोन डुअल सेल्फी कैमरा सपोर्ट करता है. इसके फ्रंट पैनल पर 32 मेगापिक्सल के दो कैमरा लेंस दिए गए हैं. प्राइमरी सेंसर एफ/2.0 अपर्चर पर काम करता है जिसमें 26एमएम फोकल लेंथ, 2एक्स पोर्टेट क्लास-अप जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं सेकेंडरी सेंसर 100° अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो एफ/2.4 अपर्चर पर काम करता है तथा एंटी-शेक एआई, ईआईएस (ईमेज स्टेबलाइजेशन) जैसे फीचर्स से लैस है.

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दमदार बैटरी

फोन में 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4500 एमएएच बैटरी है. कनेक्टिविटी के लिए, फोन में 5G, 4G, डुअल-सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ v5-3, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बीडौ और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. फोन में एक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट और एक हाई-रेस वायरलेस ऑडियो सर्टिफिकेशन भी है.

वास्तु के अनुसार घर की सीढ़ियां बनवाते समय रखें आकार, दिशा और संख्या का खास ध्यान

रायपुर. वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सीढ़ियों का निर्माण करवाते समय कुछ ऐसे नियम हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए. माना जाता है, जिस तरह व्यक्ति द्वारा जीवन में गलत कदम उठाने से असफलता प्राप्त होती है, ठीक इसी प्रकार घर बनवाते समय सीढ़ियों को गलत दिशा में बनवाने से मुसीबत आने लगती है. वहीं, वास्तु अनुसार यदि सीढ़ियों का निर्माण सही दिशा में करवाया जाए तो व्यक्ति के जीवन के सुख-समृद्धि और सफलता का कारण बनता है. वास्तु के अनुसार सीढ़ियों को बनवाते समय इसके आकार, दिशा और संख्या आदि चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए. वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के सही निर्माण के कुछ नियम बताए गए हैं, आइए जानते हैं उन्हीं कुछ नियमों के बारे में.

सीढ़ी की सही दिशा

वास्तु अनुसार घर में सीढ़ी बनाने की सबसे उचित दिशा दक्षिण-पश्चिम दिशा मानी जाती है. कोशिश करें कि घर में बनी सीढ़ियों की शुरुआत उत्तर दिशा से हो और खत्म दक्षिण दिशा में. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ईशान कोण या घर के ब्रह्स्थान पर भूलकर भी इसका निर्माण न करवाएं. वास्तु अनुसार यह एक प्रकार का दोष माना जाता है जो आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है. इसके अलावा पश्चिम और मध्य दक्षिण दिशा भी उपयुक्त मानी जाती है.

सीढ़ी का सही आकार

वास्तु अनुसार सीढ़ियों का आकार अधिक घुमावदार नहीं होना चाहिए. वास्तु में सांप के आकार वाली सीढ़ियां शुभ नहीं मानी जाती हैं क्योंकि वे ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं. जितना संभव हो सके, सीढ़ियों का आकार सीधा रखें. वास्तु अनुसार यह माना जाता है कि सही आकार आपके जीवन में सुख-सौभाग्य लेकर आता है. ऐसी सीढियां उस स्थान पर रहने वालों की तरक्की का कारण बनती है.

चरणों की संख्या

वास्तु अनुसार सीढ़ियों पर आदर्श रूप से चरणों की संख्या एक विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे कि – 5,7,9,11,15,17 आदि संख्या शुभ मानी जाती है. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सीढ़ियों का निर्माण करते समय उसको अधूरा न छोड़ें. ऐसा करना अशुभ माना जाता है.

सीढ़ी के नीचे रखें सफाई

वास्तु अनुसार घर में निर्मित सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी कूड़ा या कूड़ा दान नहीं रखना चाहिए. इसके साथ-साथ, यह भी ध्यान रखें कि आप सीढ़ियों को रोज साफ करते रहें. इस बात का भी ध्यान रखें कि सीढ़ियों के नीचे स्टडी रूम या किचन का निर्माण न करवाएं, यह घर में दरिद्रता लाता है.

सावधान! सस्ती शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम, क्रिप्टो करेंसी का लालच, हर माह करोड़ की साइबर ठगी

रायपुर. सायबर ठग लगातार करोड़ों रुपए ठगी का कारोबार कर रहे हैं. हर माह सायबर ठग प्रदेश में करोड़ रुपए की ठगी कर रहे हैं. प्रदेश में लगभग हर फेस्टिवल में लुभावने लालच देकर ठगी करने के करीब 100 मामले होते हैं. ठग एप व वेबसाइट के जरिए सस्ती शॉपिंग व बुकिंग करने का झांसा दे पैसे हड़प रहे हैं. सस्ती शॉपिंग और शॉपिंग के रिवार्ड पॉइंट देने का झांसा देकर पैसे हड़प रहे हैं. इसके अलावा घूमने वाले लोगों के लिए ट्रैवल व होटल पैकेज की बुकिंग करने का झांसा देकर ऑनलाइन पैसे हड़प रहे हैं.

वर्क फ्रॉम होम कोरोना के बाद सायबर ठग घर बैठे पैकिंग या टाइपिंग जैसे काम दिलाने का झांसा देकर लोगों को फंसा रहे हैं. अगर कोई व्यक्ति उनके झांसे में आता है तो वह तुरंत ही पहले सिक्योरिटी अमाउंट के बहाने पैसे जमा करवा लेते हैं. वर्तमान में इस तरीके से सबसे ज्यादा ठगी की जा रही है.

क्रिप्टो करेंसी में इंवेस्टमेंट बड़े लोगों से बड़ा अमाउंट ठगने के लिए बदमाश क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का झांसा दे ठगी करते हैं. फर्जी वेबसाइट या एप से लोगों को जोड़कर डेली व मंथली रिटर्न के बहाने निवेश करते हैं. शुरुआत में जुड़ने पर लोगों को ऑनलाइन ही अच्छा रिटर्न दिखाते हैं और उसके बाद अचानक वेबसाइट बंद कर दी जाती है. सेक्सटॉर्शन वीडियो कॉल करते हैं, जैसे ही आप रिसीव करेंगे तो सामने लड़की आपत्तिजनक स्थिति में रहती है. उसके साथ आपका चेहरा तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है. इसके बाद बदमाश उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं.

लालच देकर जाल में फंसाते है

साइबर अपराधी अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों को किसी प्रकार का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं. किसी भी प्रकार के आनलाइन जाब , फ्री रिचार्ज, लुभावने आफर से बचें. साइबर अपराध होने पर तुरंत अपनी शिकायत 1930 पर दर्ज करवाएं ताकि अपराधी का खाता फ्रीज किया जा सके. कभी अपना ओटीपी किसी को न दें और न निजी जानकारी किसी से साझा करें. किसी लुभावने आफर में पैसे लगाने से पहले जांच पड़ताल अवश्य करें.

सावधानियां बरते

- किसी भी तरह के लुभावने प्रस्ताव के लालच में न आएं.
- अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करते समय सतर्क रहें. किसी के साथ भी ओटीपी, पासवर्ड आदि गोपनीय जानकारी साझा न करें.
- अच्छी तरह जांच करने के बाद ही किसी भी बैंक खाते में राशि डालें.
- फेसबुक, ट्विटर आईडी का पासवर्ड स्ट्रांग रखें, सरल पासवर्ड न रखें.
- कोई रुपयों की मांग करता है, तो पहले जांच लें या मैसेज करने वाले से फोन पर संपर्क करें.

बैंक कर्मचारी कभी भी फोन पर डिटेल्स नहीं मांगते हैं.

अगर फोन पर आपसे कोई बैंक से संबंधित जानकारी मांगे तो उसे कभी नहीं दे. अगर आनलाइन ठगी से बचना चाहते तो हमेशा लुभावने प्रस्तावों से दूर रहें.

रायपुर. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने कहा है कि बाल अधिकारों की रक्षा में युवाओं की महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका है। उन्होंने नशामुक्ति, मोबाईल की लत और अन्य कई सम-सामयिक मुद्दों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए विद्यार्थियों से भारतीय समाज की आदर्श परंपराओं का पालन करने की अपील की। वे आज यहां एमिटी युनिवर्सिटी रायपुर के सभागार में गुरुवार को बाल अधिकारों के संरक्षण पर आहवान नामक जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित कर रही थीं।

बाल अधिकारों की रक्षा में युवाओं की सक्रिय भूमिकाः श्रीमती तेजकुंवर नेताम

वाईस चांसलर डॉ. पीयूष कांत पाण्डेय ने कहा कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जागरूकता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने छात्रों से बाल अधिकारों को समझ कर बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अपील की। आयोग के सचिव प्रतीक खरे द्वारा बाल अधिकारों का महत्व, अधिकार आधारित दृष्टिकोण बनाये रखने तथा बच्चों के अधिकार व प्रचलित कानूनों पर जानकारी प्रदान की। उन्होंने छात्रों को बच्चों से बात करने और उनकी निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास आदि को विकसित करने के तरीके भी बताए।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वाईस चांसलर प्रोफेसर डॉ. पीयूष कांत पाण्डेय और आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पाटले सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। बाल अधिकार पर कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के भाषा, फैशन और मनोविज्ञान विभाग द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में विधि, मीडिया तथा संचार विभाग ने सक्रियता के साथ सहभागिता की। कार्यक्रम में युनिवर्सिटी ने बाल अधिकार के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के डिप्टी प्रो वाईस चांसलर डॉ. सुरेन्द्र रहमतकर, प्रो. डॉ. बोधिसत्व आचार्य डायरेक्टर विधि विभाग, प्रो. डॉ. इंद्राणी सिंह राय तथा अन्य फैकल्टी मेम्बर उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को मिला राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड

रायपुर. उच्च शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ के "प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन" को देश की प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। विभाग को यह अवार्ड देश के कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ प्रतियोगिता करते हुए कई चरणों की प्रस्तुतिकरण, वोटिंग एवं उपलब्धियों के कारण प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने दी बधाई और शुभकामनाए

उच्च शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नैक के द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदण्डों के अनुरूप शैक्षणिक अधोसंरचना एवं अकादमिक स्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर नैक से संबद्धता प्राप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया है। कुल 211 अहर्ता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों में से 197 शासकीय महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन कराकर छत्तीसगढ़ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि कॉलेज में प्रवेश लेने वालों छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां 2018-19 में करीब 2 लाख 26 हजार 373 छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश लिया वहीं यह संख्या वर्ष 2022-23 में 48 प्रतिशत बढ़कर 3 लाख 35 हजार 139 हो गई है। जो कि 2018-19 की तुलना में एक लाख 8 हजार 766 अधिक है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विगत 4 वर्षों में कुल 33 नवीन शासकीय एवं 76 अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

उच्च शिक्षा में लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए 26 कन्या महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। अन्य महाविद्यालय में सह-अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2018-19 में जहां 91,982 छात्रों की तुलना में 1,34,391 छात्राओं ने कॉलेज में एडमिशन लिया वहीं 2022-23 में यह बढ़कर छात्रों की संख्या 1,28,310 एवं छात्राओं की संख्या 2,06,829 हो गई है। जो की छात्रों की तुलना में छात्राओं का संख्या 61 प्रतिशत अधिक है।

हाई स्कूल 9 वीं, 10 वीं एवं हायर सेकेन्डरी 11 वीं एवं 12 वीं मुख्य परीक्षा में 98.34 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण

मंत्री डॉ. टेकाम ने घोषित किया छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड का परीक्षा परिणाम

रायपुर. स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् (बोर्ड) द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का परिणाम घोषित किया। पूर्व मध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा उत्तर मध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (हाई स्कूल कक्षा 9वीं, 10वीं तथा हायर सेकेन्डरी कक्षा 11वीं, एवं 12वीं) की मुख्य परीक्षा में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 98.34 प्रतिशत रहा। शंखनाद वेदमंत्रों के उच्चारण के साथ अतिथियों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम ने परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कहा कि वे निराश ना हो फिर से मेहनत से पढ़ाई करें, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार संस्कृत के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संस्कृत विषय की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार शर्मा, राज्य गो सेवक आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत डॉ. रामसुन्दर दास, सदस्य छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् डॉ. तोयनिधि वैष्णव, सचिव श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय, सहायक संचालक परीक्षा

श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सदस्य श्रीमती निवेदिता चटर्जी सहित छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् की कर्मचारी, प्राच्य संस्कृत विद्यालयों के प्राचार्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। मंत्री डॉ. टेकाम ने परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए बताया की कक्षा पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष 9वीं में शामिल 847 परीक्षार्थियों में से 829 उत्तीर्ण हुए और परीक्षा परिणाम 97.87 प्रतिशत रहा। इसमें 519 छात्र और 310 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। कक्षा पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष 10वीं में शामिल 627 परीक्षार्थियों में से 622 उत्तीर्ण हुए और परीक्षा परिणाम 99.20 प्रतिशत रहा। इसमें 342 छात्र और 280 छात्राएं उत्तीर्ण हुई।

इसी प्रकार कक्षा उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वीं में शामिल 724 परीक्षार्थियों में से 710 उत्तीर्ण हुए और परीक्षा परिणाम 98.34 प्रतिशत रहा। इसमें 413 छात्र और 297 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। कक्षा उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष 12वीं में शामिल 750 परीक्षार्थियों में से 738 उत्तीर्ण हुए और परीक्षा परिणाम 98.40 प्रतिशत रहा। इसमें 429 छात्र और 309 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। इस प्रकार संस्कृत बोर्ड की परीक्षा में शामिल 2948 परीक्षार्थियों में से 2899 उत्तीर्ण हुए। इसमें 1703 छात्र और 1196 छात्राएं शामिल है। प्रथम श्रेणी में 1881, द्वितीय श्रेणी में 956 और तृतीय श्रेणी में 62 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए है। 28 परीक्षार्थियों को पूरक और 21 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे।

आपका अपना
ORGANIC
किराना स्टोर
ORGALIFE®
Eat Organic, Stay Healthy
ORGALIFE®
A WIDE RANGE OF CERTIFIED ORGANIC & ECO FRIENDLY PRODUCTS
CERTIFIED ORGANIC PRODUCTS
*T&C Apply
#Organic किराना स्टोर
FREE HOME DELIVERY
(Minimum Order ₹1000)
Order On ▶ www.orgalife.in Flipkart amazon
Scan & Shop Now
Shop No.15, Ram Bag Parisar,
Opp, Shri Ram Mandir, VIP Road, Raipur

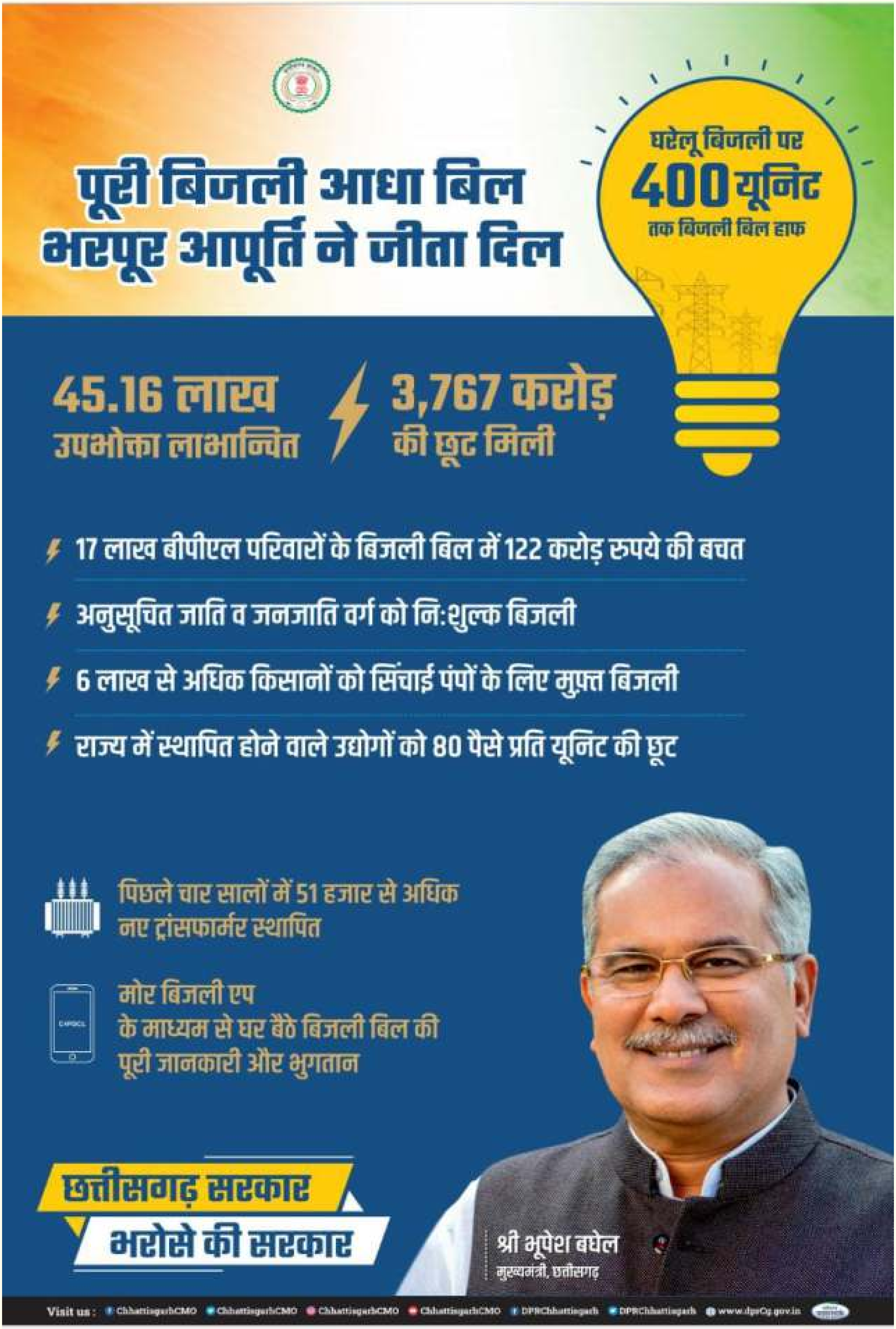

R.O. No. - 12512 / 220